PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 306 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | गुरुवार, 21 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

हक की हुंकार और 'पेट्रोल कांड' के बाद अब भी सुलग रही है गिरल माइंस !

मजदूरों की सभी मांगें जायज, विधायक भाटी का भी खौफनाक कदम, सरकार अब भी बेखौफ

मनोहरसिंह खोखर । जयपुर

लोकतंत्र में जब जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि को अपनी मांग मनवाने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़कना पड़े, तो समझ जाना चाहिए कि सिस्टम बहरा हो चुका है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट के बाहर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा उठाए गए खौफनाक कदम ने भले ही पूरे देश के मीडिया और प्रशासनिक महकमे को हिला कर रख दिया हो, लेकिन राजस्थान सरकार के कानों पर जूं तक रेंगती नहीं दिख रही है। संवेदनशीलता दिखाने के बजाय सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने और सियासी घेराबंदी करने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। हाईकोर्ट भी इस मामले में सख्ती दिखा चुका है। हालांकि सरकार भले ही बेखौफ दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष का कहना है कि 40 दिनों से भीषण गर्मी में बैठे मजदूरों की जायज मांगें (स्थानीय रोजगार और उचित मुआवजा) न मानना और फिर जनप्रतिनिधि को इस आत्मघाती कदम के लिए मजबूर करना सरकार की तानाशाही को दर्शाता है।

पेट्रोल कांड से सुलगे सवाल, जवाबों का इंतजार :

विधायक भाटी के इस आत्मघाती कदम के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर शुरू हो गया है। जहां भाटी के समर्थक इसे 'हक की हुंकार' और जनता के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण के रूप में देख रहे हैं, वहीं विरोधी खेमे और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इसे एक 'सियासी एजेंडा या साजिश' के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह कदम वाकई जनता की बेबसी का नतीजा था या फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोई सोची-समझी रणनीति?

पेट्रोल कांड से प्रशासनिक अमला हिला, पर सरकार की चुप्पी अब भी कायम

सीएम आवास की बैठक में सिवाना ग्रेनाइट पर चर्चा, गिरल माइंस पर सन्नाटा :

एक तरफ गिरल मांईस के श्रमिकों को लेकर विधायक रवींद्र सिंह बड़ी जनसभा कर बाड़मेर कूच रहे थे, तभी दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मंगलवार को ही मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिवाना में अरावली की पहाड़ियों के लिए चर्चा करते हुए उस सबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए, जबकि मुख्यमंत्री, खनिज मंत्री और खनिज सचिव में से किसी एक ने भी गिरल माइन्स मामले में किसी तरह का बयान तक देना उचित नहीं समझा। उधर विधायक भाटी खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया है। यहां तक की वार्ता करने के लिए भी सरकार ने आंमत्रित नहीं करना सरासर भाटी की अनदेखी को दर्शाता है।

सरकार बेअसर : जूं तक न रेंगने के 2 बड़े सबूत

हाईकोर्ट के आदेश की आड़

सरकार और प्रशासन इस आंदोलन को सुलझाने के बजाय राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के पीछे छिप रहे हैं, जिसमें गिरल माइंस से लिग्नाइट के परिवहन को बिना किसी बाधा के जारी रखने और पुलिस सुरक्षा देने की बात कही गई है।

शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी

जयपुर में बैठे सरकार के मुखिया और मंत्रियों की तरफ से इस गंभीर 'पेट्रोल कांड' पर अब तक कोई बड़ा आश्वासन या सहानुभूति भरा बयान सामने नहीं आया है।

श्रमिक हक की मांगें पूरी जायज :

दरअसल, यह पूरा विवाद बाड़मेर जिले के थुम्बली और गिरल गांवों में स्थित राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की आधुनिक ओपनकास्ट लिग्नाइट खदान से जुड़ा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि दशकों पहले जब खदान के लिए उनकी हजारों बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तब प्रभावित परिवारों और स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार देने का लिखित वादा हुआ था। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब खदान का नया ठेका लेने वाली कंपनी ने पिछले 20-25 वर्षों से लगातार काम कर रहे 100 से अधिक स्थानीय ड्राइवरों, ऑपरेटरों और मजदूरों को अचानक नौकरी से बाहर कर दिया। इसके विरोध में स्थानीय श्रमिक पिछले लगभग 40 दिनों से भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच गिरल माइंस के बाहर धरने पर बैठे हैं। मजदूरों की मुख्य मांगों में हटाए गए कर्मचारियों की तुरंत बहाली, श्रम कानूनों के तहत 8 घंटे की शिफ्ट निर्धारित करना और नियमों के अनुसार उचित वेतन-भत्ते देना शामिल है।

भाटी के 'सपोर्ट' में आई कांग्रेस, बीजेपी सरकार बैकफुट पर :

इस संवेदनशील घटनाक्रम के तुरंत बाद पूरी कांग्रेस खुलकर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सूबे की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा की 'पर्ची सरकार' पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से विफल हो चुकी है और सरकार की इसी तानाशाही व बहरेपन के कारण एक चुनी हुई जनता के प्रतिनिधि को आत्मदाह जैसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल पूरे बाड़मेर जिले में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

मजबूर है प्रशासन, बीच का रास्ता ही विकल्प

एक तरफ जहां जयपुर में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री बड़ी बैठकों में व्यस्त हैं, वहीं जमीनी स्तर पर बाड़मेर प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि अगर विधायक भाटी का यह आंदोलन और लंबा खिंचा, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। विपक्ष (कांग्रेस) के भारी समर्थन और सोशल मीडिया पर बढ़ते जन-आक्रोश ने भी प्रशासन को जल्द से जल्द समझौता वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। अब देखना यह है कि प्रशासन के इस 'बीच के रास्ते' वाले प्रस्ताव पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी और गिरल माइंस के मजदूर पूरी तरह सहमत होते हैं या आंदोलन का यह दूसरा चरण सरकार की मुश्किलें और बढ़ाएगा।

फर्जी बिलिंग एवं अवैध आईटीसी के जरिए 13.46 करोड़ रूपए की जीएसटी चोरी, एक गिरफ्तार

लोक टुडे। जयपुर

वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा-प्रथम द्वारा जीएसटी चोरी एवं फर्जी बिल प्रकरणों में बोगस फर्मों के लेन-देन की सघन जांच के दौरान एक कार्रवाई करते हुए जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र निवासी नितेश कुमार सिंघल को जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नितेश कुमार सिंघल पुत्र अशोक कुमार सिंघल निवासी ई-251, बैंक कॉलोनी, जयपुर द्वारा स्वयं के स्वामित्व में स्थापित फर्म मैसर्स जयपुर ट्रेडर्स का संचालन किया जा रहा था। आरोपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जयपुर स्थित विभिन्न फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग एवं अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेते हुए लगभग 13.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। प्रवर्तन शाखा-प्रथम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विशेष न्यायालय (आर्थिक अपराध), जयपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं फर्मों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। यह कार्रवाई डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त, वृत्त-सी, प्रवर्तन शाखा-प्रथम के निर्देशन में दिनेश कुमार सोनी, सहायक आयुक्त, मनोज कुमार गोरा, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी हिमांशु लोदी एवं विक्रमादित्य चौहान की टीम द्वारा संपादित की गई।

बीसीसीआई ने जारी किया घरेलू सीजन का कार्यक्रमः 1788 मैचों का होगा आयोजन, अंडर-23 टूर्नामेंट अब टी20 प्रारूप में

मुंबई

बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2026-27 के लिए 1788 मैचों का कार्यक्रम जारी किया है, जिसकी शुरुआत 23 अगस्त 2026 से दलीप ट्रॉफी के साथ होगी। इस सीजन में रणजी ट्रॉफी दो चरणों में खेली जाएगी, अंडक-23 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होंगे और महिला व जूनियर क्रिकेट को भी बड़ा मंच मिलेगा।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेलू क्रिकेट सीजन 2026-27 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आगामी घरेलू सीजन में पुरुष और महिला वर्ग की विभिन्न आयु श्रेणियों और फॉर्मेट्स में कुल 1,788 मुकाबले खेले जाएंगे। यह सीजन 23 अगस्त 2026 से प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होगा। बीसीसीआई के अनुसार, घरेलू संरचना को और मजबूत बनाने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देने तथा सभी फॉर्मेट्स में संतुलित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सीजन का कैलेंडर तैयार किया गया है।

केरल में सतीशन कैबिनेट का गठन पूराः 14 विधायक पहली बार बने मंत्री, जानें किसे मिली क्या जिम्मेदारी

तिरुवनंतपुरम।

केरल में वीडी सतीशन कैबिनेट का गठन गठबंधन के भीतर भारी खींचतान के बावजूद पूरा हो गया है। 14 नए मंत्रियों और दो महिला चेहरों के साथ आई यह नई सरकार राज्य में यूडीएफ के बड़े पीढ़ीगत बदलाव और भविष्य की युवा राजनीति का स्पष्ट संकेत है। किसे मिली कौन सी जिम्मेदारीकई दिनों तक चली राजनीतिक खींचतान, गहन विचार-विमर्श और अनिश्चितताओं के दौर के बाद केरल में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार में विभागों का आवंटन आखिरकार बुधवार को पूरा हो गया। विभागों की इस अंतिम घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत में एक नए और युवा अध्याय की औपचारिक शुरुआत हो गई है। केरल में इससे पहले साल 2011 में ओम्मन चांडी के नेतृत्व में कांग्रेस नीत यूडीएफ की सरकार बनी थी। इस नई कैबिनेट में कांग्रेस और यूडीएफ के भीतर एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार भारी संख्या में नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है।

अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास

ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की; राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई चला सकता है। इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होता है, कांग्रेस से अनुमति

लेनी होती है, या फिर सेना की सुरक्षित वापसी के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगनी होती है।

ट्रम्प ने ईरान पर बड़ा हमला टाला: ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि कतर, सऊदी अरब और श्र ने बातचीत को मौका देने के लिए हमला टालने की अपील की थी।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नया कंट्रोल सिस्टम बनाया: ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) बनाकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी। ईरान ने कहा कि बिना परमिशन गुजरना अवैध माना जाएगा।

ईरान बोला- यूरेनियम संवर्धन पर समझौता नहीं करेंगे: ईरान ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और वह किसी दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने भी कहा कि बातचीत होगी, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं।

विपक्ष बोला- युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास हो

यह वोट विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है जो कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के पास होना चाहिए। अमेरिकी संविधान में भी यही व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव को वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन लेकर आए हैं।

अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन, राजस्थान की पहली बॉक्सर बनीं, ग्लॉसगो में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

कोटा:

यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड स्थित ग्लॉसको में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी को जगह मिली है. वह 70 किलोग्राम वजन श्रेणी में मुकाबला करेंगी. अरुंधति के बेसिक कोच अशोक गौतम ने बताया कि पहली बार कोटा से कोई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयनित हुआ है. साथ ही राजस्थान से बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ खेलने जाने वाली अरुंधति पहली खिलाड़ी हैं. अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतकर राजस्थान की पहली अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता बॉक्सर बनने का गौरव भी हासिल किया है. उनका चयन हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर हुआ है. उम्मीद है कि वह विदेशी धरती पर बेहतर प्रदर्शन कर भारत का लोहा मनवाएंगी।

मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट कीःइस वीडियो का व्यूज इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन पार

इटली में एक ही कार में घूमे

रोम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर कहा- 'प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत-बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए- मेलोडी। गिफ्ट के लिए थैंक्यू ' इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) से ज्यादा बार देखा गया। वहीं एक्स पर भी इसे 74 लाख से ज्यादा व्यू मिले। पीएम मोदी अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे। वहां पीएम मेलोनी ने उनका स्वागत किया। दोनों रोम की सड़कों पर एक ही कार में घूमे और करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलोजियम का दौरा भी किया।मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी ही क्यों दी मोदी ने मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी इसलिए गिफ्ट की थी क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के नामों को जोड़कर मेलोडी (Modi + Meloni=Melodi) शब्द काफी वायरल हो गया था। असल में मेलोनी और मोदी के नामों को जोड़कर लोगों ने मजाकिया और दोस्ताना अंदाज में मेलोडी कहना शुरू कर दिया था। G20 और दूसरे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद यह शब्द इंटरनेट मीम और ट्रेंड बन गया। इसी को हल्के-फुल्के अंदाज में लेते हुए मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर टॉफी गिफ्ट की।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

सहयोग की नई भावना

ऐसे समय जब दुनिया बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और आर्थिक बिखराव का सामना कर रही है, तब उसके सामने एक बड़ा विकल्प है-क्या देश केवल अपने-अपने सीमित हितों तक सिमट जाएं या फिर ऐसे साझेदारी संबंध मजबूत करें, जो मिलकर विकास, मजबूत और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करें। जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय व्यवस्था का महत्व और भी स्पष्ट हो गया है। यह भी साफ हो चुका है कि वैश्विक शासन संस्थाओं में आज की वास्तविकताओं के अनुसार सुधार करना अब बेहद जरूरी हो गया है। आज जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक बदलाव, सप्लाई चेन में बाधाएं और ऊर्जा परिवर्तन जैसी चुनौतियां सामने हैं। इनसे निपटने के लिए सबको साथ लेकर चलने वाले सहयोग की नई भावना की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी और व्यापक चुनौतियों में से एक है। इसका असर भारत, स्वीडन समेत दुनिया की हर अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ रहा है। आज अरबों लोग बेहतर जीवन स्तर, रोजगार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं की उम्मीद रखते हैं। इसलिए विकास और अवसर पैदा करते हुए टिकाऊ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि आज के दौर की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। साथ ही, भारत दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन अभियानों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक बड़े आर्थिक विकास केंद्र और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के रूप में भारत ने निकट भविष्य के लिए दो बड़े लक्ष्य तय किए हैं-2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना। ये दोनों घरेलू लक्ष्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वैश्विक सहयोग की बदौलत, जिसमें लीडआइटी और भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ शुरू किए गए कई वैश्विक मंच शामिल हैं-जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ-भारत ग्लोबल साउथ की एक जिम्मेदार और प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। वहीं दूसरी ओर, स्वीडन यूरोप में जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कई दशक पहले लिए गए साहसिक फैसलों की वजह से वहां का बिजली ग्रिड 98 प्रतिशत तक जीवाश्म ईंधन-मुक्त हो चुका है। 1990 के बाद से स्वीडन के उत्सर्जन में एक-तिहाई से अधिक कमी आई है, जबकि इसी अवधि में उसकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना हो गया। भारत और स्वीडन की नीतियां इस व्यापक सोच को दर्शाती हैं कि जलवायु कार्रवाई केवल पर्यावरण की रक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह रोजगार और नए अवसर बढ़ा सकती है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर सकती है और लोगों का जीवन बेहतर बना सकती है। लक्ष्य सिर्फ अपने-अपने देशों के विकास को कम-कार्बन बनाना नहीं, बल्कि ऐसी साझेदारियां तैयार करना भी है, जो स्वच्छ औद्योगिकीकरण को संभव बनाएं। इसी भावना के साथ भारत और स्वीडन 17 मई को गोथेनबर्ग में मिले। हरित परिवर्तन केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं, बल्कि यह प्रतिस्पर्धा, आर्थिक मजबूती और दीर्घकालिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और स्वीडन ने 2019 में संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शुरू किए गए लीडआइटी (लीडरशिप ग्रुप फार इंडस्ट्री ट्रांजिशन) के माध्यम से इस तरह के सहयोग की अहमियत को साबित किया है। इस पहल ने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने और उन कठिन क्षेत्रों को, जहां उत्सर्जन घटाना आसान नहीं है, वैश्विक जलवायु चर्चा के केंद्र में लाने में मदद की है। इस पहल ने दिखाया है कि विकसित और विकासशील देश भरोसे, नवाचार और साझा जिम्मेदारी के आधार पर मिलकर समाधान तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज चुनौती का आकार और उसकी तात्कालिकता ऐसी है कि हमें पहले से कहीं अधिक तेज और बड़े स्तर पर आगे बढ़ना होगा। यह मंच तकनीकी साझेदारियों को तेज करने, औद्योगिक पायलट परियोजनाओं को बढ़ावा देने, टिकाऊ वित्त जुटाने, स्वच्छ ऊर्जा की मजबूत सप्लाई चेन बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कम-कार्बन उद्योग विकसित करने में उपयोगी साबित हुआ है। अगले चरण का उद्देश्य श्रमिकों के लिए नए अवसर और कौशल विकास को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। हर देश को हर समाधान खुद विकसित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर देश को अपनी विकास संबंधी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार तकनीकों को अपनाने, लागू करने और बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए। उत्सर्जन सीमाओं को नहीं मानता, इसलिए उसके समाधान भी सीमाओं में बंधे नहीं रह सकते। इसीलिए हम 2030 तक इस वैश्विक गठबंधन को और व्यापक बनाने का आह्वान करते हैं। हम अधिक देशों, विशेष रूप से नार्डिक देशों को इस प्रयास से जुड़ने और सक्रिय योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। कोई औद्योगिक परिवर्तन तभी सफल होगा, जब वह वास्तविक आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तकनीक और कम-कार्बन औद्योगिक समाधान, इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कौनसा देश किस विकल्प को प्राथमिकता देता है, यह उसकी जरूरतों पर निर्भर करेगा। कोई भी देश अकेले हर महत्वपूर्ण तकनीक, खनिज संसाधन या औद्योगिक सामग्री को सुरक्षित नहीं कर सकता। इसी तरह, कोई भी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौती का अकेले सामना नहीं कर सकता। चूंकि उत्सर्जन सीमाओं को नहीं मानता, इसलिए उसके समाधान भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होने चाहिए। हमारे सामने मौजूद अवसर केवल जलवायु नीति तक सीमित नहीं है। यह औद्योगिक सहयोग के एक नए युग को आकार देने का अवसर है। भारत और स्वीडन इस दिशा में प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में हमारा संदेश स्पष्ट है-बिखराव नहीं, बल्कि सहयोग ही साझा समृद्धि और टिकाऊ भविष्य का रास्ता तय करेगा।

> यह औद्योगिक सहयोग के एक नए युग को आकार देने का अवसर है। भारत और स्वीडन इस दिशा में प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में हमारा संदेश स्पष्ट है-बिखराव नहीं, बल्कि सहयोग ही साझा समृद्धि और टिकाऊ भविष्य का रास्ता तय करेगा।

बच्चे मन के सच्चे...बाल श्रमदान की बहस के मायने

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेलाग और बिंदास बयानों के लिए मशहूर हैं। अभी उन्होंने बाल श्रमदान को लेकर ताजा बयान दिया है। अपील की है कि बच्चों को छुई-मुई न बनाएं। उन्हें आत्मनिर्भर, मजबूत और अनुशासित बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के श्रमदान पर शिक्षकों को दंडित करने के चलन से उबरें और ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। सीएम योगी के इस बयान के चाहे जो मायने मतलब निकाले जाएं या इसे बाल श्रम बनाम बाल श्रमदान से जोड़कर नई बहस की शुरुआत मानी जाए लेकिन यह सच है कि बाल मजदूरी के लिए देश में अव्वल यूपी को 2027 तक बाल मजदूरी से मुक्त कराने की सरकार के सामने बड़ी चुनौती है ।

> उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम दान को लेकर ताजा बयान से एक नई बहस छेड़ दी है । छुई-मुई न बनाने की अपील कर उनका बच्चों को आत्मनिर्भर व अनुशासित बनाने पर जोर है । बाल श्रम के मामले में अव्वल यूपी के मुखिया के इस आह्वान के खास मायने हैं । 2027 तक यूपी को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य है । संकल्प से सिद्धि का सफर जारी है लेकिन मंजिल अभी दूर है। सरकार के सामने चुनौतियां हैं तो समाज के सामने जिम्मेदारी भी।

बाल श्रम के जख्म पर मरहम

आंकड़े बताते हैं कि देश में बाल मजदूरी का ज्यादा कोढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसकी बड़ी वजहआर्थिक व सामाजिक है। यूपी सरकार ने प्रदेश को बाल मजदूरी के मकड़जाल से निकालने का बीड़ा उठा रखा है। गरीबी व बाल मजदूरी की वजह से काफी हद तक बचपन स्कूलों तक पहुंच नहीं पाता। आर्थिक कमजोर तबके के बच्चे यदि यूपी में जैसे-तैसे स्कूल तक पहुंच भी जाते हैं, तो उनका ड्राप आउट दर काफी ज्यादा है। इसे कम करने के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, बस्ते से लेकर बाल श्रमिक विद्या योजना तक चला रखी है। बच्चों को मुफ्त जूते, यूनिफॉर्म (ड्रेस) देने का प्रावधान तो है ही, साथ ही बाल श्रमिक विद्या योजना में लड़कों को सालाना 12 हजार और लड़कियों को 14 हजार रुपये आर्थिक मदद दी जाती है। इसका असर यह हुआ कि ड्रॉप आउट दर 17 फीसदी से घटकर अब करीब 3 फीसदी पर सिमट गई है। एक आंकड़े के मुताबिक, शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य में 19 लाख बच्चों के दाखिले के लक्ष्य के विरुद्ध करीब 15 लाख बच्चों के दाखिले हो पाए हैं । शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने की मंशा से अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। 2011-12 में अनुदेशकों का मानदेय 7 हजार रुपये था, जो करीब एक दशक बाद (2022 में) महज दो हजार रुपये बढ़कर 9 हजार किया गया। स्कूल दूरदराज थे। महंगाई में इतनी कम राशि में अनुदेशकों की जीवन की गाड़ी चल पाना कठिन था। अब योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर लगभग दोगुना यानी 17 हजार रुपये कर दिया है । बेसिक शिक्षा की बेसिक जरूरत की ओर सरकार का ध्यान स्वागत योग्य है। करीब 20 हजार शिक्षकों-अनुदेशकों की जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है लेकिन पहले से 69 हजार शिक्षकों से जुड़े लंबित मामले के निष्पादन की भी उम्मीद बरकरार है ।

सजगता बनाम समस्या

बाल मजदूरी का आलम यह है कि भले बाल श्रम निषेध कानून के तहत सजा व जुर्माने का प्रावधान है लेकिन अब भी कल-कारखानों या जहां-तहां से बाल श्रमिकों के मुक्त कराने की खबरें आती रहती हैं । यूपी में करीब 9 लाख बाल श्रमिक हैं। यूपी के बाद मध्यप्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। बाल श्रम को लेकर मानवाधिकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन और संयुक्त राष्ट्र तक सजग है। यह महज संयोग ही है कि बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन को लेकर अलख जगाने के लिए पाकिस्तान की मलाला के साथ संयुक्त नोबल पुरस्कार मिला था। अमेरिका की औद्योगिक क्रांति (1820-1870) से शुरु हुआ यह बाल श्रम का खाज आज दुनिया में सबसे ज्यादा नाइजीरिया में है।

चरवाहा बनाम शिक्षक

यूपी से सटे बिहार में भी नब्बे के दशक में लालू प्रसाद ने बाल श्रम रोक कर मासूमों को स्कूल लाकर पढ़ने-पढ़ाने का सपना देखा था। बिहार के मुजफ्फरपुर के तुर्की में पहला चरवाहा विद्यालय खोला जहां गाय-बकरी चराने वाले मासूम पढ़ते थे। उनके प्रोत्साहन के लिए खाने के अलावा एक रुपये मिला करता था । चरवाहा विद्यालय के इस अनूठे प्रयोग की देश ही नहीं दुनिया भर में खूब चर्चा हुई लेकिन चरवाहा विधालय का यह नायक खुद चारा घोटाले में उलझ गया। चरवाहा विद्यालय की यह योजना बंद हो गई। उसी तुर्की में बिहार का सरकार टीईटी (बीएड) कॉलेज है, जहां अब भले बकरी चराने वाले मासूम नहीं पढ़ सके लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक आज भी तैयार होते हैं। देश में गरीब बच्चों के प्रोत्साहन के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, फिर भी बच्चों के ड्रॉप आउट दर में कमी न आना देशव्यापी चिंता का सबब है। अगले महीने (12 जून को) विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, ऐसे में यूपी से बाल श्रम बनाम बाल श्रम दान का निकला यह ताजा संदेश न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए खास मायने रखता है। उम्मीद करें कि सरकार चुनौतियों से उबरे और हम मिलकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे.... ।

विपक्ष के समक्ष खुद को बचाने का संकट

उमेश चतुर्वेदी

हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, असम में गौरव गोगोई जैसे बड़े नेताओं को मिली हार से विपक्षी खेमे में खलबली सी मच गई है। केरलम में गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत भले महसूस कर रही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नई पार्टी टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को विपक्षी एकता खासकर आइएनडीआइए की याद आने लगी है। अब वह विपक्षी एकता को मजबूत करने की बातें करने लगी हैं। हाल तक वह आइएनडीआइए की एकता से बेपरवाह थीं। आइएनडीआइए को कमजोर करने में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी कम गलतियां नहीं की हैं। राहुल गांधी का बंगाल में भाजपा की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल के ताबूत में कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विपक्षी एकता का विचार फिर से परवान चढ़ सकता है? अतीत में जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह-मात देने का खेल चला, उसे देखते हुए क्या एकता की उम्मीद अभी बची है? वर्ष 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन विपक्षी दलों में आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते वह हकीकत नहीं बन पाया। 2023 में पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी मोर्चा बनाने का फैसला तो हुआ, लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। इन सबको हाशिए पर रखने के लिए बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। वह पूरी तरह परवान चढ़ ही नहीं सकी। इसका परिणाम बीते लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। फिर विपक्षी एका में कमी के चलते हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भाजपा ने बाजी मार ली। रही-सही कसर हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है। जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्षी दल बहते हैं, उनमें एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। मुख्य रूप से यह अस्तित्व का संकट टालने का फौरी उपाय होता है। जब वे हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुटते हैं तो उन्हें अहसास होता है कि अगर एक रहते तो सत्तापक्ष पर भारी पड़ते। 1962 के आम चुनावों में पंडित नेहरू से फूलपुर की सीट पर मिली हार के बाद राममनोहर लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा था। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को चुनाव में करीब 44 प्रतिशत वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। फिर गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विपक्ष दलों में एकता की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वाममोर्चा और जनसंघ-भाजपा भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिले, वहीं भाजपा को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वाम मोर्चे को 4.45 प्रतिशत वोट मिले। इन गैर-भाजपा वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। ऐसे में विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो भाजपा को ऐसी जीत नहीं मिलती, लेकिन चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। विपक्षी दलों की समस्या यह है कि वे अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सहयोगियों से हिस्सेदारी बांटना ही नहीं चाहते। मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा भी नहीं है। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य चेहरा मानने के राह की बड़ी बाधा है। आमजन को राहुल भी कई बार अपरिपक्व नजर आते हैं। स्टालिन भी राष्ट्रीय स्तर की स्वीकार्यता के लिए अयोग्य हैं। इसी तरह केजरीवाल के पास बड़ा आधार नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की तो, उनके पास भी जमीनी राजनीति का अनुभव कम है। नीतीश पहले ही विपक्षी खेमा छोड़ चुके हैं। ममता को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त मिल गई है। अब अखिलेश को अगले साल उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में भाजपा से दो-दो हाथ करना है। भाजपा की कोशिश उन्हें तीसरी बार हराने की होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रही तो उसके सामने दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे का संकट बड़ा है। अतीत के व्यवहार से नहीं लगता कि विपक्षी दल भविष्य में कोई मजबूत मोर्चा बन सकेंगे।

> हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, असम में गौरव गोगोई जैसे बड़े नेताओं को मिली हार से विपक्षी खेमे में खलबली सी मच गई है।

तरणतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही बदस्तूर, अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए

सवाल है कि सुरक्षा मानदंडों का इस तरह से खुला उल्लंघन आखिर कैसे हो रहा है?

देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों में जगह-जगह तरणताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां सुरक्षा मानकों को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आती है। न तो इन परिसरों में प्रबंधन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है और न ही शासन-प्रशासन की ओर से जांच एवं निगरानी की जरूरत महसूस की जाती है। इसी लापरवाही के कारण कई बार तैराकी के शौकीन बच्चों और युवाओं की भी जान चली जाती है। ऐसी ही एक घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वजीराबाद के जगतपुरी इलाके में सामने आई, जहां रविवार सुबह एक तरणताल में दस साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि यह तरणताल बिना किसी अनुमति के व्यावसायिक तौर पर संचालित किया जा रहा था। यहां न तो किसी विशेषज्ञ तैराक की तैनाती की गई थी और न ही आपात स्थिति के लिए सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए गए थे। इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि जो जांच-पड़ताल पहले की जानी चाहिए थी, वह बच्चे की मौत के बाद शुरू की गई। सवाल है कि सुरक्षा मानदंडों का इस तरह से खुला उल्लंघन आखिर कैसे हो रहा है? क्या प्रशासनिक निगरानी एवं जांच तंत्र इतना कमजोर है कि कोई बिना अनुमति के ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर सकता है, जिसमें किसी की जान जाने का जोखिम हो? तरणताल में डूबने से मौत की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में कौशांबी के मंझनपुर में भी रविवार को तरणताल में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। इसी तरह पिछले सप्ताह हरियाणा के जींद जिले में भी तरणताल में एक युवक की जान चली गई थी। इन तीनों घटनाओं की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। यही नहीं, दिल्ली के जगतपुरी में तो तरणताल बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था। जाहिर है, यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव हो सकता है। सरकार को ऐसे मामलों में नियमों को कड़ाई से लागू करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए, ताकि बच्चों और युवाओं की जान के साथ खिलवाड़ न हो।

पेपर लीक मामलों में उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लाखों विद्यार्थी एक भरोसे के साथ जिस परीक्षा में अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बैठें, वह सिर्फ उनके हित में साबित हो, जिनकी पहुंच उसके प्रश्नपत्र तक हो। देश भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी को सबसे अच्छे प्रबंधन के तहत संचालित करने का दावा किया जाता रहा है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसमें जिस स्तर की गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसमें यह सवाल उठा है कि हर बार कार्रवाई के तौर पर कुछ औपचारिक और दिखावे के कदम उठा कर क्या परीक्षा के प्रश्नपत्र बाहर आने की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है? यह इस वर्ष फिर साबित हुआ है कि पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया और ऐसे जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित हो। नतीजतन, इस महीने के शुरू में आयोजित नीट के प्रश्नपत्र लीक होने की खबर आई। फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद परीक्षा को रद्द कर देना ही सबसे आखिरी उपाय माना गया, जिसकी वजह से करीब बाईस लाख विद्यार्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया। सवाल है कि इस अफसोसनाक स्थिति के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए सबसे बेहतर व्यवस्था के तहत परीक्षाओं के आयोजन का भरोसा देती रही है, क्या नीट-यूजी में प्रश्नपत्र लीक होने सहित अन्य गड़बड़ियों की निरंतरता कायम रहने की स्थिति में अब भी वह अपनी साख और प्रतिष्ठा के बने रहने का दावा कर सकती है? प्रश्नपत्र लीक होने के तथ्य सामने आने, उसके राजस्थान के कई कोचिंग संस्थानों में पहुंचने और मोटी रकम लेकर विद्यार्थियों को बेचने की खबरों के बाद सरकार ने मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी। उसके बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एनटीए की एक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है? गौरतलब है कि इस तरह की गड़बड़ियों पर काबू पाने के लिए राधाकृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट में एनटीए में ढांचागत सुधार की सिफारिश की थी। इसके अलावा, संसद में परीक्षाओं के संदर्भ में संगठित तौर पर पेपर लीक जैसी किसी गड़बड़ी के लिए दस वर्ष की कैद के प्रावधान वाला कानून पारित किया गया। साथ ही अन्य सभी कमियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों सहित आधुनिक तकनीक से लैस बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस सबके बावजूद अगर नीट-यूजी का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है और यहां तक कि परीक्षा रद्द करने की नौबत आती है, तो यह किसकी नाकामी है? अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इस व्यापक गड़बड़ी का दायरा वैसे ही निचले स्तर के आरोपियों तक सिमटा हुआ है? ऐसा नहीं है कि नीट परीक्षा के आयोजन में यह कोई पहला मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई बार अलग-अलग तरह की अनियमितताओं की खबरें आती रही हैं। सच यह है कि परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के इस रोग को खत्म करने के लिए उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

वरना पारदर्शिता के अभाव में वैसे लाखों बच्चों का भविष्य बाधित होगा, जो अपनी मेहनत के बूते परीक्षा में बैठते हैं। लातूर में ऋष्ट क्लासेस के फाउंडर शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी से कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है क्योंकि हर किसी के लिए इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने से लेकर लग्जरी गाड़ियों में बैठने तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया वह शख्स पेपर लीक मामले में आरोपी बन गया है। शिवराज मोटेगांवकर के बारे में हर कोई जानना चाहता है।

> अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है?

चिकित्सा मंत्री ने की हीटवेव प्रबंधन की समीक्षा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि हीटवेव प्रबन्धन के साथ ही अस्पतालों में गर्मियों को लेकर मरीजों के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने भीषण गर्मी के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में छाया-पानी के समुचित प्रबंध के साथ उपाचर में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हीटवेव, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, बजट घोषणा की अनुपालना, एचपीवी वैक्सीन की प्रगति सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से बनाए गए नोडल अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कर अस्पतालों में हीटवेव से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी है। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को हीट-स्ट्रोक के लिए अलग से बेड आरक्षित करने, आवश्यक दवाइयों (जैसे ORS, IV

Fluids आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन कूलिंग उपकरणों एवं किट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि मरीजों और परिजनों के लिए शीतल पेयजल, प्रतीक्षालयों में छाया एवं कूलिंग सुविधाओं के पूर्ण इंतजाम हों। खींवसर ने कहा कि तेजी से बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव का व्यापक और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक संबंधी बीमारियों के उपचार के प्रोटोकॉल की जानकारी वाले स्टाफ को तैनात रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग ने विगत समय में रिकॉर्ड भर्तियां कर सुदूर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी समुचित स्टाफ उपलब्ध करवाया है।

इससे स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संस्थान प्रभारी राज हेल्थ पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना प्राथमिकता के साथ अपडेट करें, ताकि आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों का तुरंत प्रभाव से नियोजन किया जा सके और मानव संसाधन का सही उपयोग संभव हो। मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने प्रदेश में एचपीवी वैक्सीन के कवरेज को बढ़ाने की दिशा में और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण स्थानीय स्तर पर आशा-एएनएम के साथ पहले से ही एक कार्ययोजना बनाते हुए कैम्प आयोजित किए जाएं।

न्यूज इन बॉक्स

डीजीपी बोले- पुलिस की फील्ड विजिबिलिटी बढ़ाएं

कहा- तीन महीने में 1 साल से ज्यादा लंबित कोई भी मामला नहीं रहे; क्राइम रिव्यू मीटिंग में दिए निर्देश

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेशभर के रेंज आईजी, पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कानून-व्यवस्था, संगठित अपराध, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में डीजीपी शर्मा ने कहा- राज्य सरकार अवैध खनन, बजरी परिवहन और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।

कान्स फिल्म-फेस्टिवल में घूंघट में पहुंचीं जयपुर की रुचि गुर्जर

सोशल मीडिया पर लिखा- मेरा घूंघट चुप्पी नहीं, विरोध है; पिछले साल दिखा था पीएम मोदी लुक

जयपुर(नि.सं.)। 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जयपुर की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री रुचि गुर्जर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में आ गईं। इस बार वह घूंघट ओढ़कर फेस्टिवल में पहुंचीं, उन्होंने महिलाओं की आजादी और पहचान को लेकर एक मजबूत सामाजिक संदेश दिया। सोशल मीडिया पर लिखा- मेरा घूंघट चुप्पी नहीं, विरोध है।

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेड कारपेट्स में शुमार कान्स फिल्म फेस्टिवल में रुचि गुर्जर का पारंपरिक राजस्थानी घूंघट लुक चर्चा का केंद्र बन गया। रुचि इससे पहले भी कान्स में अपने अलग लुक को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं, पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उनकी तस्वीर वाले विशेष नेकलेस को पहनकर सुर्खियों में रही थीं।

राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 5024 नए आवासों को मिली मंजूरी

- **80 शहरों की परियोजनाओं के लिए 125.60 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत**
- **आवासों को पूरा करने और ग्राउंडिंग में राजस्थान का देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मुख्य सचिव ने जताई प्रसन्नता**

जयपुर(नि.सं.)। प्रधानमंत्री के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण के लिये 2.50 लाख रूपये की अनुदान राशि मिलेगी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रूपये के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके तहत कुल 125.60 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जावेगी। राज्य सरकार से अनुमोदित किये गये 5024 आवासों की अन्तिम स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार की आगामी 26 मई को आयोजित होने वाली सीएसएमसी बैठक में अन्तिम स्वीकृति मिलेगी। बैठक के दौरान पीएमएवाई-यू एवं कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीनाने बताया कि आवासों की मंजूरी के अतिरिक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि रू. 39.60 करोड़ के क्षमता संवर्धन प्लान का भारत सरकार से अनुमोदन हेतु अभिशंसा की गई।

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज पहुंचे संभागीय आयुक्त

प्रसूताओं के इलाज के बारे में जानकारी ली

जयपुर(नि.सं.)। कोटा संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक एवं नवीन चिकित्सालय का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में रेजिडेंट चिकित्सकों से वार्ता कर उनका पक्ष सुना तथा उनकी सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया तथा अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को संविदा सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। अग्रवाल ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में भर्ती 6 प्रसूताओं के स्वास्थ्य संबंधी रेकार्ड एवं चल रहे इलाज के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली तथा प्रसूताओं के परिजनों से मुलाकात की। संभागीय आयुक्त ने न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर संविदा गार्ड के रेकार्ड चेक किए। निर्धारित रेकार्ड के अनुसार सुबह की पारी में 45 तथा दोपहर 2 बजे से 25 सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था चिकित्सालय में होनी थी।

ई-स्कूटर डीलरशिप का झांसा देकर 25.37 लाख की ठगी

लॉन्चिंग तो कराई, पर एक भी गाड़ी नहीं भेजी; जयपुर के कारोबारी पर केस

अजमेर(वि.सं.)। अजमेर की एक फर्म से ई-स्कूटर डीलरशिप दिलाने के नाम पर 25.37 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर अलवर गेट थाना पुलिस ने जयपुर निवासी कारोबारी राजा अजमानी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांधी नगर, नाका मदार स्थित आर.सी. मार्केटिंग एवं श्री वर्धमान इंटरप्राइजेज की पार्टनर रेखा जैन और छाया जैन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया कि जयपुर निवासी राजा अजमानी ने खुद को PIXXEL Appliances इन्फोसिस्टम्स का संचालक बताकर ई-टू व्हीलर, पार्ट्स और सर्विसिंग का कारोबार पूरे राजस्थान में करने का प्रस्ताव दिया था।

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

उज्जवला-गैस उपभोक्ताओं को अब हर साल कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

नहीं तो रुक सकती है सब्सिडी, 73 लाख राजस्थानी होंगे प्रभावित

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान समेत देशभर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोकी दी जाएगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगर लाभार्थी साल में 7 रिफिल लेने के बाद 8वीं रिफिल अगर बुक करवाता है तो उसे पहले वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, तभी उसे सब्सिडी की राशि मिलेगी।

राजस्थान में 73 लाख उपभोक्ता

राजस्थान में वर्तमान में तीनों तेल कंपनियों के करीब 73 लाख उपभोक्ता उज्जवला कनेक्शन वाले हैं, जिनको केन्द्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है।

इन उपभोक्ताओं को सरकार साल में 9 सिलेंडर लेने तक ये सब्सिडी देती है।

30 जून तक करवाना अनिवार्य

मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की है, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी आधार आधारित बायोमेट्रिक केवाईसी नहीं करवाई है। तय समय सीमा तक वेरिफिकेशन नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी जून के बाद रोक दी जाएगी।

14-साल की बच्ची को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ

भैंस को निकालने के लिए पानी में उतरी थी; चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण

धौलपुर(वि.सं.)। धौलपुर जिले के राजघाट गांव में 14 साल की बच्ची को मगरमच्छ चंबल नदी में खींच ले गया। मगरमच्छ बच्ची को नदी के दूसरे किनारे पर ले गया। इस दौरान वहां मौजूद दूसरी लड़कियां घबरा गईं और शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बालिका को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद राजघाट और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार, राजघाट निवासी दीनदयाल की बेटी भारती (14) रोजाना की तरह बुधवार सुबह करीब 11 बजे मवेशियों को पानी पिलाने के लिए चंबल नदी पर गई थी।

डीग पुलिस की मेगा कार्रवाई

5 करोड़ से अधिक की लैपटॉप चोरी का पर्दाफाश, 464 नए लैपटॉप के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार

डीग(वि.सं.)। पुलिस जिला डीग में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के कुशल निर्देशन में थाना पहाड़ी पुलिस और जिला विशेष टीम (DST) ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 4 करोड़ 14 लाख रुपये की कीमत के 464 चोरी के नए लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मारुति बलेनो कार बरामद की है। महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ा है वारदात का कनेक्शन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लैपटॉप चोरी और इस बड़ी साजिश की यह वारदात महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पारशिवनी थाना इलाके में हुई थी, जिसके संबंध में वहां मामला दर्ज है। डीग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे षड्यंत्र के मुख्य आरोपी अजरूद्दीन उर्फ हजरूद्दीन को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से मोटोरोला (Motorola) कंपनी के सीलबंद 464 नए लैपटॉप बरामद किए गए हैं, जिन्हें वह कौड़ियों के दाम खपाने की फिराक में था।

'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड' डब्ल्यूएचओ ने राजस्थान के उत्कृष्ट प्रयासों को सराहा

राजस्थान को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर मिला प्रथम सम्मान

सरकार की जनस्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम यह सम्मान: मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान ने तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वर्ष 2026 के 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड' के तहत राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया है। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में राजस्थान को यह प्रतिष्ठित सम्मान डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष 2025-26 में तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य सरकार की जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता, प्रभावी नीतियों तथा तम्बाकू मुक्त राजस्थान के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन विशेषकर युवाओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। यह सम्मान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, चिकित्सा कर्मियों एवं सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है।

राजस्थान बना तम्बाकू मुक्ति का मॉडल - चिकित्सा मंत्री

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान ने तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में देशभर में एक मॉडल स्थापित किया है। राज्य में तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं का व्यापक विस्तार किया गया है, जिसका लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी जनजागरूकता और प्रभावी कानून प्रवर्तन के माध्यम से तम्बाकू

नियंत्रण अभियान को और मजबूत करेगी।

प्रदेश में 500 से अधिक तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र संचालित

राज्य में ब्लॉक स्तर तक 500 से अधिक तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों को जियो-टैग कर आमजन की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति निकटतम केंद्र तक आसानी से पहुंच सके।

एक तरफ पेट्रोल दूसरी तरफ फर्ज...

हैट्स ऑफ और सैल्यूट एएसपी 'आर्य'

एएसपी नितेश आर्य ने उस संकट के क्षण में असाधारण त्वरितता, सूझबूझ और फुर्ती का दिया परिचय, चौतरफा हो रही सराहना

वह चंद सेकंड... जब थम गईं सबकी सांसें

यह महज कुछ सेकंड का वाकया था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स की सांसें हलक में अटक गई थीं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बदन से पेट्रोल टपक रहा था और चेहरे पर जबरदस्त आक्रोश। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय, वर्दी का फर्ज निभा रहे एएसपी नितेश आर्य ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शेर के सामने चीते जैसी छलांग लगाई। एक तरफ पेट्रोल से भीगा विधायक खुद को आग लगाने को आतुर था, तो दूसरी तरफ एएसपी आर्य ने उन्हें अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि विधायक चाहकर भी हाथ नहीं हिला सके। इसी सूझबूझ ने बाड़मेर को इतिहास के एक काले पन्ने में दर्ज होने से बचा लिया।

सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी:

ऐसे संवेदनशील और हाई-वोल्टेज मामलों में मौके पर मौजूद सबसे सीनियर फील्ड ऑफिसर को तुरंत निर्णय लेना होता है। एएसपी आर्य ने एक कुशल लीडर की तरह बिना समय गंवाए खुद आगे बढ़कर स्थिति को संभाला और भाटी को सुरक्षित कलेक्ट्रेट के अंदर ले गए। इस कार्यवाही के वीडियो सोश्यल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है, जिनकी हर तरफ सराहना हो रही है।

बड़ी अनहोनी को टाला:

विधायक का चेहरा और पूरा बदन पेट्रोल से भीगा था और वे बेहद आक्रोश में थे। एएसपी आर्य ने फुर्ती से उन्हें पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके पकड़ लिया। जिससे एक बड़ा और जानलेवा हादसा होते-होते रह गया।

नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन

एएसपी आर्य ने न सिर्फ एक पुलिस अधिकारी बल्कि एक कुशल लीडर की तरह ऑन-स्पॉट फैसला लिया। उत्तेजित भीड़ के सामने खुद को फ्रंटलाइन पर रखकर उन्होंने पूरी पुलिस टीम का हौसला बढ़ाया।

आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारण

बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 38-39 दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पिछले 14 दिनों से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे। सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों और मजदूरों में भारी आक्रोश था। भाटी ने एक दिन पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी थी। अपनी घोषणा के मुताबिक वे करीब 500 गाड़ियों के विशाल काफिले और हजारों समर्थकों के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) का घेराव करने के लिए रवाना हुए। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट से करीब 1 किलोमीटर पहले ही भारी बैरिकेड्स और बसें लगाकर काफिले को रोक दिया। जब भाटी और उनकी भीड़ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंची, तो वहां तैनात एएसपी नितेश आर्य और पुलिस बल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। प्रशासनिक उदासीनता और रोके जाने से नाराज विधायक भाटी ने अचानक अपने बैग से पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर उड़ेल लिया। इस अप्रत्याशित कदम से वहां मौजूद पुलिस, मीडिया और समर्थकों में हड़कंप और अफरा-तफरी मच गई। ठीक सामने खड़े अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) नितेश आर्य ने अद्भुत फुर्ती दिखाई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर विधायक भाटी को पीछे से कसकर पकड़ लिया। वहीं मौके पर मुस्तैद एक कांस्टेबल ने तुरंत भाटी के हाथ से पेट्रोल की बोतल और माचिस झपटी। समर्थकों ने भी तुरंत कपड़ों से भाटी के बदन से पेट्रोल पोंछा। बड़ा हादसा टलने के बाद एएसपी आर्य और अन्य कमांडो ने सुरक्षा घेरा बनाया। पुलिसकर्मियों ने उत्तेजित भीड़ से बचाते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लगभग उठाकर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर सुरक्षित भेज दिया ताकि माहौल और ज्यादा न बिगड़े। इसके तुरंत बाद कलेक्ट्रेट के सारे मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और चप्पे-चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया।

खेताराम बृजवाल। बाड़मेर

यह राजस्थान की सियासत और पुलिसिंग के इतिहास का वह चंद सेकंड का मंजर था, जिसे बाड़मेर कभी नहीं भूलेगा। एक तरफ जन-आंदोलन के उग्र मोड़ पर खड़ा, पेट्रोल से पूरी तरह भीगा हुआ युवा विधायक था, जो प्रशासनिक बेरुखी से क्षुब्ध होकर आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने को आतुर था। दूसरी तरफ, खाकी का गौरव और अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित एएसपी नितेश आर्य खड़े थे। जैसे ही पेट्रोल की महक हवा में फैली, वैसे ही राजनीति के 'शेर' के सामने फर्ज का 'चीता' तनकर खड़ा हो गया। बिना अपनी जान की परवाह किए बिना यह सोचे कि पेट्रोल की एक चिंगारी उन्हें भी चपेट में ले सकती है, एएसपी आर्य ने विधायक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह मुकाबला किसी टकराव का नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की जान बचाने और कानून की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के बीच 'फर्ज' की जीत का था।

संकट के समय त्वरित फैसले लेने के महारथी हैं एएसपी आर्य :

आरपीएस नितेश आर्य अपनी सख्त कानून-व्यवस्था, संवेदनशील पुलिसिंग और संकट के समय ऑन-स्पॉट त्वरित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। बाड़मेर के इस 'पेट्रोल कांड' से पहले भी वे अपने करियर में कई मौकों पर अपनी असाधारण सूझबूझ और फुर्ती का लोहा मनवा चुके हैं।

एएसपी के साथ साए की तरह तैनात कांस्टेबल, जिसने झपटी पेट्रोल की बोतल :

कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जब माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, तब एएसपी नितेश आर्य के ठीक बगल में बाड़मेर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से खड़े थे। जैसे ही विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर पेट्रोल डाला, एएसपी आर्य ने उन्हें पीछे से जकड़ा। ठीक उसी क्षण, वहां मुस्तैद कांस्टेबल दानाराम ने बिना एक सेकंड गंवाए चीते जैसी झपट्टा मारते हुए विधायक के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। यह एक्शन इतना त्वरित था कि विधायक को माचिस निकालने का मौका ही नहीं मिला। यदि कांस्टेबल का यह सटीक रिस्पॉन्स न होता, तो पेट्रोल से भीगे विधायक और उन्हें पकड़े हुए एएसपी, दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस कांस्टेबल की सजगता ने साबित कर दिया कि खाकी का हर एक जवान जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहता है।

डीडवाना में बेहतरीन सेवाएं:

बाड़मेर से पहले नितेश आर्य डीडवाना में बतौर एएसपी तैनात थे। वहां भी उन्होंने कई जटिल अपराधों का पर्दाफाश करने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और सख्त अनुशासन लागू करने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई थी।

हाई-अलर्ट और संवेदनशील ऑपरेशन

हाल ही में जब बाड़मेर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल मिला था, तब भी एएसपी नितेश आर्य ने भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ महज डेढ़ घंटे में पूरे परिसर को खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया और स्थिति को बेहद सूझबूझ से संभाला था।

सामाजिक सरोकार और समाज सेवा:

फील्ड पर जितने सख्त नितेश आर्य अपराधियों के लिए हैं, आम जनता के लिए वे उतने ही संवेदनशील हैं। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश करते हुए सपत्नीक देहदान की घोषणा की है और वे खुद 60 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं।

फर्ज के प्रति अटूट निष्ठा:

पुलिस विभाग के सहकर्मियों का कहना है कि एएसपी आर्य हमेशा से ही 'अग्रिम पंक्ति' पर रहकर कमान संभालने में विश्वास रखते हैं, जिसकी गवाही कलेक्ट्रेट के सामने की यह ताजा घटना भी दे रही है।

सूझबूझ की चौतरफा सराहना :

इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद बाड़मेर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक हलकों तक में एएसपी नितेश आर्य और बाड़मेर पुलिस के त्वरित रिस्पॉन्स की जमकर सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने पलक झपकते ही वह एक्शन नहीं लिया होता, तो बाड़मेर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट की आग में झुलस सकता था।